

हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का नरिदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक (प्रवाह की एक इकाई जो 1 घन फुट प्रतिसेकंड के बराबर है) अधिशेष जल छोड़ने की अनुमति दे दी तथा हरियाणा सरकार को नरिदेश दिया कि वह [हथनी कुंड बैराज](#) से दलिली में इस जल का नरिबाध प्रवाह सुनरिचित करे, ताकि [पेयजल संकट](#) का समाधान हो सके।

मुख्य बदि:

- न्यायालय ने [ऊपरी यमुना नदी बोर्ड \(UYRB\)](#) को हरियाणा के [हथनी कुंड](#) में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लयि कहा।
- राष्ट्रीय राजधानी में [जल की कमी के बीच दलिली सरकार](#) ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से तत्काल अतरिकित जल प्राप्त करने के लयि [सर्वोच्च न्यायालय](#) में याचिका दायर की थी।
- अपनी याचिका में दलिली सरकार ने कहा कि वह दलिली के नागरिकों द्वारा झेली जा रही गंभीर जल कमी के कारण याचिका दायर करने के लयि बाध्य है, जो उत्तर भारत, विशेषकर दलिली में जारी [भीषण गर्मी](#) के कारण उत्पन्न हुई है।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)

- ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, नदी वकिस और गंगा संरक्षण वभिग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- दनांक 12 मई, 1994 को बेसनि राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली के मुख्यमंत्रियों द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोज्य सतही प्रवाह के बँटवारे के [समझौता ज्ञापन \(MoU\)](#) पर हस्ताक्षर कयि गए
 - MoU में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) नामक एक बोर्ड के नरिमाण का प्रावधान है।